वीरांगनाओं के साथ न्याय के लिए डटे रहे किरोड़ी मीणा

जयपुर। वीरांगनाओं के लिए न्याय की माँग को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार दूसरे दिन शहीद स्मारक पर जारी रहा। डॉक्टर मीणा ने कहा कि जिस शासन में शहीदों की वीरांगनाओं का अपमान होता है वह सत्ता नष्ट होती है। सरकार की वादाखिलाफी से ख़फ़ा डॉक्टर किरोड़ी मीणा वीरांगनाओं और उनके परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। शहीद जीतराम

- **धरना दूसरे दिन भी जारी, सरकार से विफल रही वार्ता**

शहीद स्मारक स्थित धरना स्थल पर वीरांगनाओं के साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे। उनके साथ विधायक मदन दिलावर व संदीप शर्मा भी मौजूद थे।

गुर्जर की पत्नी सुन्दरी देवी, शहीद रोहिताश लाम्बा की पत्नी मंजू जाट, शहीद हेमराज मीना की पत्नी मधुबाला मीना धरने पर डॉक्टर मीणा के साथ है। डॉक्टर मीना ने कहा वीरांगनाओं के जायज़ माँगों के सम्मान में दूसरे दिन धरने पर बैठा हूं। शहीदों का अपमान करने वाली अशोक गहलोत सरकार को वीरांगनों का सम्मान करना सीखना चाहिए।

धरना स्थल पर बुधवार को राज्य मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा पहुँचे। उन्होंने आश्वासन दिया की वीरांगनाओं की माँगें मानी जाएगी कल मुख्यमंत्री से बात करूँगा। धरना स्थल पर उप प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़, विधायक मदन दिलावर, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, विधायक गोपी चंद मीना, विधायक संतोष बावरी, विधायक संदीप शर्मा, पूर्व विधायक हीरालाल नागर पहुँचे ओर वीरांगनाओं की माँगो का समर्थन किया।

डॉक्टर किरोड़ी ने तीनों वीरांगनाओं के साथ शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा से मुलाक़ात की। वार्ता में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी पर वीरांगनाओं की मुख्य माँगों पर सहमति नहीं बन पाई और वार्ता विफल हो गई। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवान की वीरांगनाओं की माँगें थी की सड़क निर्माण, स्कूल का शहीद के नाम नामकरण ओर आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने शहीदों के दाह संस्कार के समय की थी अब सरकार को वायदा निभाना चाहिए।

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसमें राजनीति ना करके देश के लिए बलिदान देने वाले वीर ज़वानो के परिजनों की जायज़ माँगों को तुरंत मान लेना चाहिए। इस मौक़े पर वीरांगनाओं का कहना है सरकार के द्वारा की गई घोषणा पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ओर जिन पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। श्याम क़रीब सात बजे वीरांगनाओं के साथ सैकड़ों युवाओं ने केंडिल मार्च किया पुलिस प्रशासन सकते में आया बड़ी मुश्किल से प्रशासन की बात मान कर शहीद स्मारक के अंदर घुसे प्रशासन ने चैन की साँस ली।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी वीरांगनाओं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने का मुद्दा सदन में उठाया। राठौड़ ने कहा कि सरकार की ओर से मंत्री ने कहा था कि सिर्फ एक वीरांगना धरने पर बैठी है और उसके देवर को नौकरी देने पर सहमति नहीं बनी है, बाकी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। जबकि हकीकत यह है कि चार वीरांगनाएं और उनके बच्चे धरने पर बैठे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने जो वायदे उनके साथ किये हैं उन्हें पूरा किया जाये। कुछ जगहों पर शहीद की मूर्ति लगनी बाकी है तो कुछ जगहों पर सड़क निर्माण व अन्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं। मेरा सदन से आग्रह है कि शहीदों के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सरकार उनकी मांगों पर तुरंत निर्णय ले।

डॉ. सतीश पूनियां ने 4 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव की तैयारियों पर चर्चा की

जयपुर। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, लंबित भर्तियां, सम्पूर्ण किसान कर्जमाफी, महिला सुरक्षा इत्यादि जनहित के मुद्दों को लेकर 4 मार्च को कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ विशाल विधानसभा घेराव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जयपुर के नगर निगमों के पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों के साथ तैयारियों को लेकर संवाद किया।

- **भाजपा विधायक दल की बैठक में सदन में उठाए जाने वाले प्रदेश के जनहित के मुद्दों और 4 मार्च के विधानसभा घेराव आंदोलन को लेकर सतीश पूनियां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधायकों के साथ चर्चा की**

बैठक में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा, जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट इत्यादि भी उपस्थित रहे। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा में उठाए जाने वाले प्रदेश के जनहित के मुद्दों और 4 मार्च के विधानसभा घेराव आंदोलन को लेकर सतीश पूनियां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधायकों के साथ चर्चा की।

मीडिया से बातचीत में डॉ. पूनियां ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने साढ़े चार वर्षों में सदन की गरिमा तो गिराई ही है, लेकिन उसके साथ यह सदन जवाबदेह होता है, जितने मुद्दे विधायकों के द्वारा चाहे वह सत्तापक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उठाये जाते हैं।

विधानसभा में राज्य सरकार के स्तर पर कोई संजीदगी नहीं देखी जा रही है, यहां सदन में जब बहुत गंभीर चर्चा होती है तो उस पर भी इनके मंत्री बहुत केजुअल जवाब देते हैं या फिर जवाब दे ही नहीं पाते हैं। इससे यह साफ दिखता है कि जब सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं होती है तो वह शब्दों के रूप में प्रकट हो जाती है, जनहित के मुद्दों को भाजपा सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठा रही है और प्रदेश के हालात हर मोर्चे पर इतने विफल हैं कि कांग्रेस सरकार के विधायकों के द्वारा भी सदन में प्रदेश के अराजक हालात की स्थिति रखी जा रही है, जो सबके सामने है।हालांकि यह जुगाड़ की सरकार है, इसमें जो लोग बैठे हैं उनकी परफॉरमेंस धरातल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो पूरे प्रदेश में एंटी इनकमबेंसी है, वह सरकार के साथ-साथ इनके मंत्री और विधायकों के खिलाफ भी है।

वकीलों का बहिष्कार जारी, हाईकोर्ट में सुनवाई टली

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और नए वकीलों को मानदेय देने से जुड़े मामले में सुनवाई एक दिन के लिए टल गई। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सचिवालय में मीटिंग चल रही है और उसमें कई एएजी भी गए हुए हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी जाए। जिस पर अदालत ने सुनवाई टाल दी। हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और जोधपुर में वकील जुगराज सिंह की हत्या को लेकर कई दिनों से चल रहे न्यायिक कार्य बहिष्कार पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इस प्रसंज्ञान मामले में भी गुरुवार को ही सुनवाई होगी। वहीं निचली कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, जेडीए कोर्ट व अन्य कोर्ट में वकीलों का न्यायिक कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर राज्य सरकार से जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। जिसमें हाईकोर्ट बार के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता विकास सोमानी सहित अन्य वकील शामिल हुए।

वहीं दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव सहित डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव की टीम बुधवार को मुख्यमंत्री से मिले। हाईकोर्ट बार के महासचिव बलराम वशिष्ठ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बुधवार शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। दूसरी ओर बीसीआर ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित की है।

सोने-चांदी के जेवर समेत दो शातिर नकबजन दबोचे

जयपुर (कासं)। सदर थाना पुलिस ने सोना-चांदी चुराने के मामले में दो शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही हैं।

डीसीपी (अपराध) ज्येष्ठा मैत्रयी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद मोईन शास्त्री नगर और अनिल कुमार स्वामी स्वामी बस्ती चांदपोल बाहर संजय सर्किल के रहने वाले है। पुलिस ने बताया कि जयपुर शहर में घर में घुसकर नकबजनी की वारदात के बाद एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी, पुलिस निरीक्षक मुनिन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने मोहम्मद मोईन और अनिल कुमार स्वामी को गिरफ्तार कर लिया।

शहीदों के परिजनों का सहयोग नहीं करते अफसर : गुढ़ा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान शहीदों के परिजनों को लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठा। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि अफसर शहीदों के परिजनों का बिल्कुल सहयोग नहीं करते। विधायक संदीप शर्मा के सवाल के जवाब में गुढ़ा ने कहा कि शहीदों के परिजनों को पैकेज के तहत 25 बीघा जमीन और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 बीघा जमीन जहां अलॉट करते हैं, कई शहीदों के परिजन मौके पर जमीन देखकर उसे लेना पसंद नहीं करते, वह जमीन उन्हें पसंद नहीं आती। शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार के प्रावधान के हिसाब से कई प्रावधान हैं, लेकिन अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं।

दुष्कर्मी को बीस साल की सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कजोड़ मल उर्फ कमल को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सार-समाचार

कनिष्ठ सहायक घूस लेते गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर में कृषि उपज मंडी समिति सूरजपोल के कनिष्ठ सहायक को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी अब उसके आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि संसोधित मंडी लाइसेंस जारी करने की एवज में अनिल कुमार सक्सेना, कनिष्ठ सहायक नियमन शाखा, कृषि उपज मंडी समिति सूरजपोल जयपुर की ओर पांच हजार रुपए की रिश्वत राशी मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक चन्द्र शर्मा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। बुधवार को उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी ने मय टीम के ट्रेप की कार्रवाई करते हुए शांति नगर गोपालपुरा बाईपास हाल कनिष्ठ सहायक नियम शाखा, कृषि उपज मंडी समिति सूरजपोल के अनिल कुमार सक्सैना को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

जाट महाकुंभ का आयोजन 5 मार्च को

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में 5 मार्च आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ में समाज का विकास, किसानों की खेती समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, प्रदेश महासचिव मदन चौधरी और आईजी महेंद्र चौधरी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में जाट समाज को सशक्त बनाने जाटों में सामाजिक एकजुटता कायम करने एवं समरसता लाने के लिए काम करना, जातिगत जनगणना का संकल्प पारित करना, सरकार से वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करवाना, समाज के समस्त विधि सम्मत संगठनों के सक्रिय पदाधिकारियों को शामिल करना तथा ओबीसी आरक्षण की वर्तमान विसंगतियों को दूर करवाकर उसे जाति के अनुपात में लागू करवाने का मुख्य एजेंड़ा रहेगा। मीडिया प्रभारी शीशराम कटेवा ने बताया कि महाकुंभ में एक राज्य राष्ट्रीय स्तरीय गर्वनिंग कौंसिल का गठन करना, सामाजिक कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज बाल विवाह दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना, छात्र-छात्राओं के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मंथन करना, रोजगार प्राप्त करने में मदद हेतु समाज के शिक्षाविदों विचार को बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्तियों को शामिल कर एक थिंक टैंक तैयार करना शामिल है। इस अवसर पर जाट महाकुंभ का पोस्टर का भी विमोचन किया गया।

जे.के.के. में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति

जयपुर, (का.सं.)। जवाहर कला केंद्र के मुक्ताकाश मंच पर रंग राजस्थान व् पिंकफेस्ट के संयुक्त तत्वावधान में रंग उल्लास कार्यमक्रम का आयोजन किया गया जिसमे सहयोगी संस्था के रूप में जयपुर सिटीजन फोरम, एॅम एॅफ़ जे सी एॅफ़ ऑर्गन डोनेशन व् मैसेज संस्थान ने जयपुर वासियो से किसी जरुरत मंद के जीवन में आनंद रंग बरसाने हेतु, अंग दान को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत आईआईआईकेडीएम की छात्राओं द्वारा गोविंदम गोकुला नंदन गोपालम वंदना के प्रस्तुति से किया गया इस मोके पर शुभम टीम रंग उल्लास द्वारा चंग-डफ की थाप पर आमिर खुसरो के कलाम मोहे अपने ही रंग में रंग दे और होली के सुरीले फाग गायन से भाव विभोर कर दिया। मुख्य अतिथि राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कार्यक्रम की सराहना की।

झोटवाड़ा में लगेगा पशु आहार प्लांट

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि राजफैड द्वारा पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशुआहार की आपूर्ति के लिए आधुनिक संसाधनों से युक्त 100 मीट्रिक टन का पशुआहार प्लान्ट झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजफैड के पशुआहार की अपनी एक विशेष पहचान है एवं पशुपालकों द्वारा इसकी मांग हमेशा रहती है। गुहा ने बुधवार को झोटवाडा में स्थित राजफैड के पशुआहार प्लान्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राजफैड का पशुआहार प्लान्ट वर्ष 1971 में स्थापित किया था। इस प्लान्ट का अधिकतम कार्य मैनुअल ऑपरेशन से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक प्लान्ट से अधिक मात्रा में पशुआहार का उत्पादन किया जाएगा ताकि पशुपालकों की मांग को समय पर पूरा किया जा सके।

'ओ.बी.सी. आरक्षण की विसंगति दूर हो'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के स्टेट कॉर्डिनेटर डी.आर.यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहा वर्तमान 21 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को 27 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये, क्योंकि हाल ही में न्यायालय के निर्णय के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने में अब कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के समुदायों की जनसंख्या लगभग 55-56 प्रतिशत है फिर भी उन्हें 21 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। अत: आरक्षण की सीमा को 21 से 27 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये।

लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू ने कार्यभार संभाला

जयपुर, (का.सं.)। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने सप्त शक्ति कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित प्रेरणा स्थल पर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक स्कूल बीजापुर के पूर्व छात्र एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के स्नातक, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए।जनरल ऑफिसर, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज, महू से स्नातक हैं। इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूनाइटेड किंगडम से अपना नेशनल डिफेंस कॉलेज किया और नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल, मोंटेरे, यूएसए में काउंटर टेररिज्म में प्रतिष्ठित मास्टर्स प्रोग्राम

बी.एस.राजू

में भी भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में सेवाएं दी है।

कोर्ट की ऑर्डर शीट बदलने वाले रीडर को 38 साल बाद सजा

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर प्रथम ने वर्ष 1984 में बेदखली से जुड़े वाद में कोर्ट की ऑर्डर शीट बदलने वाले तत्कालीन रीडर हरबंस खुराना को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने प्रकरण में न्यायालय की ऑर्डर शीट को बदलकर रिकॉर्ड में कूटरचना कर एवं न्यायिक कार्यवाही में झूठी साक्ष्य देने और उसे पत्रावली में शामिल कर असल रूप में प्रयोग करने का गंभीर आरोप है। अभियुक्त के कृत्य से न्यायालय की कार्यवाही की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे में उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं अदालत ने ट्रायल के दौरान सह आरोपी सूरज नारायण की मौत होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर चुकी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 1984 में एसीएमएम कोर्ट क्रम-4 में बेदखली से जुड़ा दावा लंबित चल रहा था। इस दौरान पांच जनवरी 1984 की ऑर्डर शीट के जरिए अभियुक्त प्रतिवादी सूरज नारायण का बेदखली के विरुद्ध अधिकार समाप्त किया गया था। वहीं तत्कालीन रीडर हरबंस ने मिलीभगत कर नई ऑर्डर शीट जारी कर सूरज के बेदखली के विरुद्ध प्रतिरखा के अधिकार को समाप्त होने की बात को हटा दिया। मामला सामने आने पर वर्ष 1992 में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं 25 जून 1993 को हरबंस लाल खुराना ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी दौरान उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तकनीकी आधार पर हरबंस के खिलाफ लिए गए प्रसंज्ञान को गलत मानते हुए कहा कि मामला संबंधित मजिस्ट्रेट के परिवाद पर दर्ज नहीं हुआ है। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की गई।

राजस्थान में बीते चार सालों में शिक्षा का सम्पूर्ण ढांचा चरमराया : वासुदेव देवनानी

'प्रदेश की स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक-संसाधन नहीं, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का बेड़ागर्क किया'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन में शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस की शैक्षिक नीतियों की जमकर पोल खोली। देवनानी ने कहा कि पिछले 4 सालों में शिक्षा का सम्पूर्ण ढांचा चरमरा गया है। शैक्षिणक संस्थानों में न शिक्षक, न अशैक्षिणक स्टाफ, न संसाधन और न ही शिक्षा को लेकर राज्य सरकार का कोई विजन ही है। प्रदेश में शिक्षा का बेडागर्क हो चुका है। बहस में सत्ता पक्ष व विपक्ष के तमाम विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में अध्यापकों की कमी, स्कूल भवन नहीं होने की कमियां गिनाईं।

देवनानी ने कहा कि महात्मा गांधी का कभी भी अंग्रेजी से संबंध नहीं रहा। वे स्वभाषा के समर्थक रहे लेकिन सरकार ने हिन्दी माध्यम स्कूलों को बंद कर उनके नाम पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले। सरकार ने बिना योजना के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की रेवडियां बांट दी, जिसके परिणाम ढाक के तीन पात ही रहे। करीब 3400 स्कूलें खोलने की बजट घोषणा पूरी हुई नहीं कि इस बजट में 1000 और नए विद्यालय खोलने का राग अलाप दिया गया। इन स्कूलों में 10 हजार शिक्षक पद रिक्त है। संविदा पर भर्ती का राग अलापा उसमें भी असफल रहे। सरकार की विद्या संबल योजना न विद्या दे पाई और न ही संबल ही दे पाई। अध्यापकों के अभाव में बच्चे न घर के रहे न घाट के ऐसे में प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड हो रहा है।

देवनानी ने कहा कि विदेशों में हिंदी माध्यम में रामायण, गीता व महाभारत पढाई जा रही है जबकि प्रदेश में प्रार्थनासभा में योगाभ्यास तक बंद कर दिए। सत्ता में आने पर हम स्कूलों में रामायण, महाभारत और गीता पढाने के साथ प्रार्थनासभा में योगाभ्यास पुन: प्रारंभ कराएंगे।

देवनानी ने कहा कि प्रदेश की स्कूल-कॉलेजों का हाल ऐसा है कि जहां बच्चे कम है, वहां अध्यापक ज्यादा है और जहां बच्चे ज्यादा, वहां अध्यापक कम है। स्टाफिंग पैटर्न के अभाव में अध्यापकों की कमी के कारण आए दिन स्कूलों पर ताले जड़ने की शिकायतें मिल रही है। करीब 17100 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में से 12 हजार में तो अनिवार्य विषयों के व्याख्याता पद तक स्वीकृत तक नहीं है। वर्तमान में संयुक्त निदेशक से लेकर प्रिंसिपल शिखक तक 1 लाख से अधिक पद रिक्त है। परिणाम न निरीक्षण, न पर्यवेक्षक और न शिक्षण ही हो रहा है।

देवनानी ने बताया कि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इसी माह से प्रारंभ हो रही है जबकि पाठयक्रम पूरा नहीं हुआ है। इस शैक्षिणक सत्र में कार्यदिवस केवल 131 ही हुए है जबकि 180 होने चाहिए ऐसी स्थिति में स्कूलों में पढाई कैसे हो? समझ से परे है। सरकार ने अभी तक कम्प्यूटर शिक्षक नहीं लगाए। स्कूलों में लगे 50 करोड के कम्प्यूटर कबड होकर धूलफांक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 22 हजार स्कूल मर्ज किए। तब विपक्ष के नाते कांग्रेस ने खूब हल्ला करते हुए सत्ता में आने पर पुन: खोलने की बात कही लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद केवल 1250 ही खोल पाए उसमें से भी 151 विद्यालयों में शून्य और 580 में 25 से कम नामांकन होने के कारण पुन: बंद कराना इनकी मजबूरी हो गई है।

- **महात्मा गांधी स्वभाषा के समर्थक, फिर भी सरकार ने उनके नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला**
- **'भाजपा सत्ता में आते ही स्कूलों में योगाभ्यास, रामायण-महाभारत और गीता की पढ़ाई कराएगी'**

उन्होंने कहा कि सीकर, अलवर, भरतपुर व बांसवाडा विश्वविद्यालय में एक भी शैक्षिणक पद पर नियुक्ति नहीं है। अजमेर स्थित एमडीएस में 48 में 34, कोटा में 78 में 56 व बीकानेर में 77 में 60 पद खाली है। स्कील यूनिवर्सिटी में 2 वर्ष में न कुलपति और न स्थनीय स्टाफ दिया गया। जोधपुर फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तो किया लेकिन एक्ट अनुमोदित नहीं किया गया। एजेसीटीई-यूजीसी से मान्यता नहीं मिली है। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में कोई सहायक नहीं है। केवल खाता खुला रखने के लिए 1000-2000 रूपए दर्शाए गए। महिला योग्यता छात्रवृति, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृति, शोध, ललित कला एवं पूर्व सैनिक आश्रितों के बच्चों को छात्रवृति के लिए बजट सिर्फ 1 लाख रूपए देना खुला मजाक है।

देवनानी ने कहा कि 4 निजी विश्वविद्यालयों को खोलने में फर्जीवाडा किया गया। गुरूकुल, सौरभ, ड्यूज एवं व्यास यूनिवर्सिटी का असफर और संबंधित कमेटी ने आंख मूंदकर सत्यापन किया। भ्रष्टाचार का बडा खेला खेला गया। पेपर लीक प्रकरण पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि आयुक्तालय में कार्यरत राजीव स्टडी सर्कल से जुडे शिक्षक डॉ बनेसिंह, सुभाष यादव और बी.एस.बैरवा को दिखावे के लिए निलंबित किया गया। अब वापिस बहाल करके आयुक्तालय में बैठा दिया गया।

विधायक ने सवाल ही गलत पूछा है : गुढ़ा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक पानाचंद मेघवाल ने होमगार्डों को नियमित भर्ती से संबंधित पूरक प्रश्न पूछा। इस पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि विधायक ने सवाल ही गलत पूछा है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड सरकारी नौकर नहीं होते वे स्वयं सेवक होते हैं। इसलिये इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। इन्हें वेतन व अन्य परिलाभ नहीं दिये जा सकते। विधायक ने सवाल ही गलत पूछा है।

नेटबंदी के खिलाफ एससी में याचिका

जयपुर। प्रदेश में बडी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान इंटरनेट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। छाया रानी की इस जनहित याचिका पर होली बाद सुनवाई होगी। प्रदेश में बीते दिनों आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के दौरान 11 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने को जनहित याचिका में आधार बनाया गया है। पीआईएल में कहा गया कि इंटरनेट बंद करने का संभागीय आयुक्तों का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरनेट बंद करना अवैध है। राज्य सरकार के अफसर अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश दे रहे हैं।

सी.एम.के सलाहकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है : सी.पी.जोशी

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सिरोही से निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक युवक को मर्डर के झूठे मुकदमे का मामला उठाया। लोढ़ा ने मंत्री टीकाराम जूली से कहा कि आपने जब सिरोही जेल का निरीक्षण किया था, तब मर्डर के झूठे मुकदमे में फंसाए गए आदिवासी से बात हुई थी। जिस दिन मर्डर हुआ वह जेल में था, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, आपने दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में क्यों नहीं लिखा? इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने संयम लोढ़ा से कहा मुख्यमंत्री के सलाहकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस पर सदन में जमकर ठहाके लगे।

प्रदेश में तीन नए संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को तीन नए करोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच किसी भी मरीज के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 10 हो गए है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में बुधवार को उदयपुर में तीन नए संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले राज्य में मंगलवार को दो रोगी मिले थे। इधर आज राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में एक भी संक्रमित के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 10 हो गए हैं।